आयकर आयुक्त, केरला, एर्नाकुलम

बनाम

वी. दामोदरन, त्रिवेंद्रम

15 अक्टूबर, 1979

[एन.एल. अंतवालिया और आर.एस. पाठक, जे.जे.]

भारतीय आयकर अधिनियम, 1922- धारा 2 (6ए)(ई) - "संचित लाभ" का अर्थान्वयन यदि इसमें वर्तमान लाभ शामिल हैं - धारा 256 (1)- दायरा।

निर्धारिती एक कंपनी का प्रबंध निदेशक था, जिसका मूल्यांकन वर्ष 1959-60 के लिए मूल रूप से 43407/- रुपये की कुल आय पर किया गया था। इसके बाद आयकर अधिकारी को पता चला कि निर्धारिती कंपनी से पैसे निकाल रहा था और उन राशियों को अधिनियम की धारा 2(6ए)(ई) के तहत लाभांश के रूप में माना जा सकता था, उन्होंने मूल्यांकन फिर से खोला। इसके बाद हुई मूल्यांकन कार्यवाही में, निर्धारिती ने दावा किया कि कंपनी का संचित लाभ केवल 1050 रुपये था और उस राशि को अकेले अधिनियम की धारा 2(6ए)(ई) के तहत लाभांश के रूप में माना जा सकता है। यह आंकड़ा इस आधार पर तैयार किया गया था कि कर के प्रावधान के रूप में 11,000 रुपये और लाभांश के प्रावधान के रूप में 6,900 रुपये को लाभ और हानि खाते में 18,950 रुपये की शेष राशि के

विरुद्ध समायोजित किया जाना था। आयकर अधिकारी ने करदाता की दलील खारिज कर दी। अपीलीय सहायक आयुक्त ने निर्धारिती द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। दूसरी अपील में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्धारिती के दावे को बरकरार रखा कि अधिनियम की धारा 2(6ए)(ई) में "संचित लाभ" शब्द को वर्तमान लाभ सहित नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसने इस तर्क को खारिज कर दिया कि दोनों "संचित" का आंकड़ा निर्धारित करने में 11,000 रुपये और 6,900 रुपये की राशि को ध्यान में रखा जाना था! मुनाफ़ा"। इसने "संचित लाभ" 18,950 रुपये निर्धारित किया। राजस्व ने इस प्रश्न पर उच्च न्यायालय से एक संदर्भ प्राप्त किया: "क्या अपीलीय न्यायाधिकरण यह मानने में कानूनी रूप से सही था कि संचित लाभ में अधिनियम की धारा 2(6ए) के प्रयोजन के लिए "वर्तमान लाभ" शामिल नहीं होगा।"

निर्धारिती के कहने पर एक दूसरा प्रश्न उच्च न्यायालय को भेजा गया था: "क्या ट्रिब्यूनल यह मानने में सही था कि अधिनियम की धारा 2(6ए) के प्रयोजन के लिए 18,950 रुपये संचित लाभ है।" उच्च न्यायालय ने दोनों प्रश्नों का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में दिया, पहला प्रश्न सकारात्मक और दूसरा प्रश्न नकारात्मक था।

इस न्यायालय में अपील करने पर अभिनिर्धारित किया :

1. "वर्तमान लाभ" अर्थात, उस वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, जिसमें निर्धारिती को ऋण दिए गए थे, को अधिनियम की धारा 2(6

ए) (ई) के अर्थ के तहत कंपनी के "संचित लाभ" में शामिल नहीं माना जा सकता है। [947 जी-948 ई]

आय-कर आयुक्त, मद्रास बनाम एम.वी. मुरुगप्पन और अन्य एंड, (1970) 77 आई.टी.आर. 818 अनुसरण किया।

2. अपीलीय न्यायाधिकरण दूसरे प्रश्न को संदर्भित करने में सक्षम नहीं था, और उस सीमा तक संदर्भ को शून्य माना जाना चाहिए। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256(1) करदाता या आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, अपीलीय न्यायाधिकरण में आवेदन करने पर धारा 254 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न को उच्च न्यायालय को संदर्भित करने का अधिकार देती है। यह स्पष्ट है कि क़ानून स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय के संदर्भ की इच्छा रखने वाले पक्ष द्वारा उस संबंध में एक आवेदन पर विचार करता है। आवेदन को एक निर्धारित सीमा अवधि के भीतर दाखिल करना होगा। यदि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो इस प्रकार अस्वीकृत आवेदक ही उच्च न्यायालय में आवेदन करने का हकदार है। आयकर नियम, 1962 के नियम 48 द्वारा निर्धारित संदर्भ आवेदन के फॉर्म में आवेदक को विशेष रूप से कानून के उन प्रश्नों को बताने की आवश्यकता होती है जिन्हें वह उच्च न्यायालय में भेजना चाहता है। प्रत्येक मामले में, संदर्भ के लिए आवेदन करने वाला पक्ष ही कानून के उन प्रश्नों को निर्दिष्ट करने का हकदार है जिन्हें संदर्भित किया जाना

चाहिए। क़ानून कहीं भी गैर-आवेदक (सुविधा के लिए यहां इस्तेमाल किया गया एक वाक्यांश) को आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर कानून के प्रश्नों का संदर्भ मांगने का अधिकार नहीं देता है। [950 ए, सी-डी ई, एफ-जी और 952 ई]।

जो पक्ष व्यथित है और जो उच्च न्यायालय में संदर्भ चाहता है, उसे उस उद्देश्य के लिए एक संदर्भ आवेदन दायर करना होगा। दूसरे पक्ष द्वारा दायर संदर्भ आवेदन को उसके दावे का आधार बनाना उसके लिए खुला नहीं है कि, उसके द्वारा मांगे गए कानून के प्रश्न को संदर्भित किया जाना चाहिए। लेकिन पीड़ित पक्ष द्वारा दायर एक संदर्भ, आवेदन पर यह गैर-आवेदक के लिए खुला है जो अपील के परिणाम से व्यथित नहीं है, वह कानून के उन सवालों का संदर्भ मांग सकता है जो अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील में नकारात्मक प्रस्तुतियों पर उत्पन्न होते हैं। [951 ए-बी। सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2099/1972

केरल उच्च न्यायालय द्वारा आई.टी.आर. संख्या 88/1969 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 18-1-1972 से उत्पन्न।

बी. बी. आहूजा और सुश्री ए. सुभाशिनी, अपीलार्थी की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं ।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

पाठक, न्यायाधिपति.-

यह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 2(6ए)(ई) में "संचित लाभ" शब्दों की व्याख्या करने वाले केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 261 के तहत प्रमाण पत्र द्वारा एक अपील है।

निर्धारिती आर.के.वी.मोटर्स एंड टिम्बर (पी) लिमिटेड नामक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रबंध निदेशक है। कंपनी अपनी पुस्तकों में उनसे संबंधित एक खाता रखती है। खातों से पता चला कि 31 मार्च, 1958 को कंपनी द्वारा उन्हें 36,546.17 रुपये की राशि देय थी। जनवरी, 1959 में वे पहली बार कंपनी के 3,757.04 रुपये के ऋणी बने: उनके चित्र बढ़ते गए और 31 मार्च, 1959 तक कुल राशि बढ़ गई उनके द्वारा देय राशि 25,107.22 एनपी थी। यह बताना भी प्रासंगिक है कि 31 मार्च, 1958 को कंपनी की बैलेंस शीट में 18,950.98 एनपी का शुद्ध लाभ दिखाया गया था।

निर्धारिती का मूल्यांकन मूल रूप से निर्धारण वर्ष 1959-60 (प्रासंगिक पिछला वर्ष 31 मार्च, 1959 को समाप्त होने वाला वर्ष है) के लिए 43,407 रुपये की कुल आय पर किया गया था। इसके बाद, आयकर अधिकारी को पता चला कि निर्धारिती कंपनी से पैसे निकाल रहा था, और इस विश्वास के साथ कि उन राशियों को भारतीय आयकर की धारा 2(6ए)(ई) के तहत "लाभांश" माना जा सकता था। अधिनियम, 1922, उन्होंने

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के आधार पर मूल्यांकन को फिर से खोला। इसके बाद हुई मूल्यांकन कार्यवाही में, निर्धारिती ने दावा किया कि कंपनी का संचित लाभ केवल 1,050 रुपये था, और उस राशि को अकेले धारा 2(6ए)(ई) के तहत "लाभांश" माना जा सकता है। यह आंकड़ा इस आधार पर तैयार किया गया था कि कर के प्रावधान के रूप में 11,000 रुपये और लाभांश के प्रावधान के रूप में 6,900 रुपये की राशि को लाभ और हानि खाते में 18,950 रुपये की शेष राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाना था। आयकर अधिकारी ने निर्धारिती के तर्क को दोहराया और धारा 2(6ए)(ई) के तहत लाभांश के रूप में 25,107 रुपये की राशि निर्धारित की। वह 31 मार्च, 1959 को समाप्त होने वाले खाता वर्ष के लिए कंपनी के वर्तमान मुनाफे को शामिल करके इस आंकड़े पर पहुंचे। अपीलीय सहायक आयुक्त ने निर्धारिती द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने, दूसरी अपील में, निर्धारिती के दावे को बरकरार रखा कि धारा 2(6ए) (ई) में "संचित लाभ" शब्द को वर्तमान लाभ सहित नहीं माना जा सकता है, लेकिन उसने इस तर्क को खारिज कर दिया कि दो रकम संचित लाभ का आंकड़ा निर्धारित करने में 11,000 रुपये और 6,900 रुपये को ध्यान में रखा जाना था। तदनुसार, इसने संचित लाभ 18,950 रुपये निर्धारित किया।

राजस्व ने केरल उच्च न्यायालय में संदर्भ के लिए आवेदन किया और उसके कहने पर ट्रिब्यूनल ने निम्नलिखित प्रश्न उच्च न्यायालय को भेजा:

> "क्या इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, अपीलीय न्यायाधिकरण यह मानने में कानूनी रूप से सही था कि संचित लाभ में भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 2(6ए) के प्रयोजन के लिए वर्तमान लाभ शामिल नहीं होगा?"

निर्धारिती ने एक प्रश्न शामिल करने का भी अनुरोध किया, और इसलिए उच्च न्यायालय को भेजा गया दूसरा प्रश्न था:

> "क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल यह मानने में सही था कि 18,950 रुपये भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा (6ए) के प्रयोजन के लिए संचित लाभ है?"

उच्च न्यायालय ने 18 जनवरी, 1972 के अपने निर्णय द्वारा पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक और दूसरे प्रश्न का नकारात्मक दिया है, दोनों प्रश्नों का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में दिया गया है। और अब, राजस्व द्वारा वर्तमान अपील।

हमने राजस्व के लिए श्री बी.बी.आहूजा को सुना है। निर्धारिती की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 में मूल रूप से "लाभांश" की कोई परिभाषा नहीं थी, और उस शब्द का अर्थ कंपनियों से संबंधित कानून के तहत रखे गए अर्थ तक ही सीमित था। भारतीय आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1939 की धारा 2 द्वारा, भारतीय विधानमंडल ने अधिनियम की धारा 2 में उप-धारा (6ए) शामिल की और एक समावेशी परिभाषा निर्धारित की। इसके बाद उप-धारा के कुछ खंडों में संशोधन किया गया, और उनके अंतिम रूप में धारा 2(6ए)(सी) और धारा 2(6ए)(ई) को इस प्रकार पढ़ा गया:

"6(ए) "लाभांश" में शामिल हैं –

(सी) किसी कंपनी द्वारा उसके परिसमापन पर शेयरधारकों को किया गया कोई भी वितरण, इस हद तक कि वितरण उसके परिसमापन से ठीक पहले कंपनी के संचित मुनाफे के लिए जिम्मेदार है, चाहे वह पूंजीकृत हो या नहीं।

ई) किसी कंपनी द्वारा कोई भी भुगतान, जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता धारा 23ए के अर्थ के तहत पर्याप्त रूप से रुचि रखती है, किसी भी राशि का (चाहे कंपनी की संपत्ति के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करने के लिए या अन्यथा) अग्रिम या जोआन के माध्यम से किसी शेयरधारक को या किसी शेयरधारक की ओर से या उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसी किसी भी कंपनी द्वारा कोई भुगतान, जिस हद

तक कंपनी के पास किसी भी मामले में संचित लाभ होता है।"

सवाल यह है कि क्या उस वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, जिसमें निर्धारिती को ऋण दिए गए थे, यानी वर्तमान लाभ, को कंपनी के संचित मुनाफे में शामिल माना जा सकता है। यह देखा जाएगा कि अभिव्यक्ति "संचित लाभ" अधिनियम की धारा 2(6ए)(सी) में आती है। **गिरधरदास एंड कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, अहमदाबाद [1957] 31 आई टी आर. 82, 88** में उस खंड की व्याख्या करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा: "विधानमंडल द्वारा लगाई गई सीमा यह है कि लाभ को सबसे पहले मौजूदा मुनाफे के विपरीत संचित किया जाना चाहिए...।" **आयकर आयुक्त मद्रास बनाम एम.वी.मुरुगप्पन और अन्य** आई एल.आर.[1967] 2 मद्रास 256 और **आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम ए.एम.एम.वी.वल्लिअम्माई अची और अन्य** [1966] 62 आई टी आर 382 के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया। इसने "संचित लाभ" की अवधारणा का विश्लेषण किया और उस संबंध में विशेष रूप से इसहाक और रिच जेजे की टिप्पणियों का उल्लेख किया। **हूपर एंड हैरिसन लिमिटेड (परिसमापन में) बनाम संघीय कराधान आयुक्त, 33 सी एल आर 458, 480** में, जो हॉलिन्स बनाम एलन **(1866) 14 डब्ल्यू.आर. 980** और स्प्राउल बनाम बाउच**, (1885) 29 सी एच डी 635** और अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त बनाम ब्लोल्ट **(1921) 2 ए.सी. 171** पर निर्भर

था, जहां वर्तमान मुनाफे और संचित मुनाफे के बीच अंतर को ग्राफिक रूप से सामने लाया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय की इस न्यायालय द्वारा आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम एम.वी.मुरुगप्पन और अन्य **(1970) 77 आई.टी.आर. 818** में अपील में पुष्टि की गई थी और यह देखा गया था कि "मुनाफा या वह वर्ष जिसके दौरान कंपनी को बंद करने का आदेश दिया गया था। संचित लाभ लाभांश का हिस्सा नहीं थे।" इसके बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने **आयकर आयुक्त (केंद्रीय) बॉम्बे बनाम पी.के. बदियानी (1970) 76 आई टी आर 369** के मामले में, अधिनियम की धारा 2(6ए}(ई) की व्याख्या करते हुए, उसी निर्माण को लागू किया और माना कि उस खंड में "संचित लाभ" की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। मतलब लाभ जो लेखांकन वर्ष से पहले जमा हुआ था, जिसमें आय लाभ और लाभ का आकलन किया जा रहा था, जबकि वर्तमान लाभ का मतलब लेखांकन वर्ष का मुनाफा होगा। हाल के एक मामले में, आयकर आयुक्त, मद्रास टीआई बनाम जी. शंकरन, **(1978) 111 आई.टी.आर. 220 में** मद्रास उच्च न्यायालय ने फिर से पुष्टि की है कि धारा 2(6ए)(ई) में अभिव्यक्ति "संचित लाभ" वर्तमान लाभ में नहीं ली जा सकती है।

स्थिति अच्छी तरह से सुलझी हुई प्रतीत होती है। टी. सुंदरम चेट्टियार बनाम आयकर आयुक्त, मद्रास और टी. मनिकवासगम चेट्टियार बनाम आयकर आयुक्त, मद्रास **(1963) 49 आई.टी.आर. 287** को छोड़कर, जिसमें अनुपात स्पष्ट नहीं है, न्यायिक निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला ने यह

विचार किया है कि शब्द " भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 6(2ए) में संचित लाभ" को वर्तमान लाभ में शामिल नहीं माना जा सकता है। हम उस दृष्टिकोण से सहमत हैं, उपरोक्त मामलों में प्रचलित तर्कों द्वारा इस संबंध में आश्वस्त किया जा रहा है। "संचित लाभ" और "वर्तमान लाभ" के बीच अंतर लंबे समय से कायम है, और जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने हूपर एंड हैरिसन लिमिटेड (परिसमापन में) (सुप्रा) में देखा, यह अच्छी तरह से जाना जाता है न्यायिक निर्णय और व्यापारिक दुनिया में एक सदी से भी अधिक समय से। इसके अलावा, एम.वी.मुरुगप्पन (सुप्रा) में इस न्यायालय ने यह भी विचार किया है कि वर्तमान मुनाफे को संचित मुनाफे में शामिल नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अब देश का स्थापित कानून है। राजस्व की ओर से एक आकर्षक निवेदन उठाया गया कि भारत के विधि आयोग की बारहवीं रिपोर्ट (पेज B24 आइटम 17) में, रिपोर्ट के लेखक मानते हैं कि विधानमंडल का इरादा धारा 2 में अभिव्यक्ति "संचित लाभ" में वर्तमान लाभ को शामिल करना था(6ए) और वह वर्तमान परिभाषा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(22) के स्पष्टीकरण 2 द्वारा "संचित लाभ" केवल यह स्पष्ट करता है कि वास्तविक इरादा क्या था। जिस दृष्टिकोण को हमने पसंद किया है, हम उस समर्पण से सहमत नहीं हैं।

तदनुसार, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने पहले प्रश्न का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के विरुद्ध देकर सही था।

दूसरा सवाल यह है कि क्या 31, मार्च 1958 के संचित लाभ की गणना करते समय कर और लाभांश के भुगतान के प्रावधान को ध्यान में रखा जा सकता है। राजस्व का तर्क है कि इस प्रश्न को निर्धारिती के कहने पर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय में नहीं भेजा जाना चाहिए था क्योंकि निर्धारिती द्वारा कोई संदर्भ आवेदन नहीं किया गया था। बताया गया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एकमात्र संदर्भ आवेदन आयकर आयुक्त द्वारा दायर किया गया संदर्भ आवेदन था। हमारी राय है कि राजस्व सही है. जब मामले का विवरण तैयार किया जा रहा था, तब राजस्व द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष आपत्ति की गई थी, लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण ने गिरधरदास एंड कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, अहमदाबाद (1957) 31 आई.टी.आर. 87 पर भरोसा करते हुए आपत्ति को खारिज कर दिया। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि राजस्व ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया कि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उसे दिया गया संदर्भ दूसरे प्रश्न के संबंध में अक्षम था। हालाँकि, आपत्ति संदर्भ की क्षमता से संबंधित है, इस हद तक कि यह दूसरे प्रश्न को कवर करती है और इसलिए, उस प्रश्न पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, हमारी राय है कि उस सवाल को हमारे सामने उठाने के लिए राजस्व का अधिकार है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256(1) निर्धारिती या आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, अपीलीय न्यायाधिकरण में आवेदन करने और

अपीलीय द्वारा दिए गए आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न को उच्च न्यायालय में संदर्भित करने का अधिकार देती है। धारा 254 के तहत न्यायाधिकरण. ऐसे आवेदन करने के लिए नकल की अवधि निर्धारित है। यदि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो आवेदक निर्धारित सीमा अवधि के भीतर फिर से उच्च न्यायालय में आवेदन करने का हकदार है, और यदि उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय की शुद्धता से संतुष्ट नहीं है, तो वह आवेदन कर सकता है। अपीलीय न्यायाधिकरण से मामले को बताने और उसे संदर्भित करने की अपेक्षा करें। यह स्पष्ट है कि क़ानून स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय के संदर्भ की इच्छा रखने वाले पक्ष द्वारा उस संबंध में एक आवेदन पर विचार करता है। आवेदन को एक निर्धारित सीमा अवधि के भीतर दाखिल करना होगा। यदि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो इस प्रकार अस्वीकृत आवेदक ही उच्च न्यायालय में आवेदन करने का हकदार है। यदि अपीलीय न्यायाधिकरण अपने यहां किए गए आवेदन को अनुमति देता है, तो धारा 256(1) के अनुसार उसे मामले का विवरण तैयार करना होगा और इसे उच्च न्यायालय में भेजना होगा। मामले का विवरण आवेदक द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर तैयार किया गया है, जिसे उस आवेदन में कानून के प्रश्नों को निर्दिष्ट करना होगा, जो उसका दावा है, धारा 254 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से उत्पन्न हुए हैं। आयकर नियम, 1962 के नियम 48 द्वारा निर्धारित संदर्भ आवेदन के फॉर्म में आवेदक को

विशेष रूप से कानून के उन प्रश्नों को बताने की आवश्यकता होती है जिन्हें वह उच्च न्यायालय में भेजना चाहता है। उचित मामलों में, उसे अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा संदर्भ आवेदन की सुनवाई में कानून के और प्रश्न उठाने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन हर मामले में, संदर्भ के लिए आवेदन करने वाला पक्ष ही कानून के उन प्रश्नों को निर्दिष्ट करने का हकदार है जिन्हें संदर्भित किया जाना चाहिए। कानून में कहीं भी हमें आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर कानून के प्रश्नों का संदर्भ मांगने के लिए गैर-आवेदक (सुविधा के लिए यहां इस्तेमाल किया गया एक वाक्यांश) का अधिकार नहीं मिलता है।

इस संबंध में, मामलों की दो श्रेणियों की परिकल्पना की जा सकती है। एक में ऐसे मामले शामिल हैं जहां धारा 254 के तहत न्यायाधिकरण के आदेश ने आंशिक रूप से एक पक्ष के खिलाफ और आंशिक रूप से दूसरे पक्ष के खिलाफ अपील का फैसला किया है। ऐसा हो सकता है कि अपील में एक ही विषय वस्तु शामिल हो या अपील में एक से अधिक स्वतंत्र दावे हों। पूर्व में, एक पक्ष राहत दिए जाने से व्यथित हो सकता है, भले ही आंशिक हो, जबकि दूसरा पक्ष पूर्ण राहत देने से इनकार करने से व्यथित हो सकता है। उत्तरार्द्ध में, विवाद में व्यक्तिगत वस्तुओं के संदर्भ में राहत दी या अस्वीकार की जा सकती है, और तदनुसार एक पक्ष या दूसरा पीड़ित होगा। किसी भी मामले में, जो पक्ष व्यथित है और जो उच्च न्यायालय में संदर्भ चाहता है, उसे उस उद्देश्य के लिए एक संदर्भ आवेदन दायर करना

होगा। दूसरे पक्ष द्वारा दायर संदर्भ आवेदन को अपने दावे का आधार बनाना उसके लिए खुला नहीं है कि उसके द्वारा मांगे गए कानून के प्रश्न को संदर्भित किया जाना चाहिए। दूसरी श्रेणी में वे मामले शामिल हैं जहां धारा 254 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया आदेश पूरी तरह से एक पक्ष के पक्ष में संचालित होता है, हालांकि आदेश देने के दौरान अपीलीय न्यायाधिकरण ने उस पक्ष द्वारा उठाए गए कानून के कुछ बिंदुओं को अस्वीकार कर दिया हो सकता है। अपील के परिणाम से व्यथित पक्ष नहीं होने के कारण, उस पक्ष के लिए संदर्भ आवेदन दाखिल करना संभव नहीं है। लेकिन पीड़ित पक्ष द्वारा एक संदर्भ आवेदन दायर किए जाने पर, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा मामले को उच्च न्यायालय में संदर्भित करने के लिए सहमत होने की स्थिति में, यह गैर-आवेदक के लिए खुला है कि वह कानून के उन प्रश्नों का भी संदर्भ मांग सके जो उठते हैं। अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील में इसकी प्रस्तुतियों को अस्वीकार कर दिया गया। यह, जैसा कि था, अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश का समर्थन करने के लिए जीतने वाली पार्टी के अधिकार को मान्यता देता है, अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उठाए गए लेकिन उसके द्वारा अस्वीकार किए गए आधारों पर भी।

इसलिए, वे दो श्रेणियां हैं, एक जिसमें कोई अनावेदक इसके द्वारा सुझाए गए कानून के प्रश्नों का संदर्भ मांग सकता है और दूसरा जिसमें वह नहीं पूछ सकता है। जिस हद तक न्यायालयों ने इन दो श्रेणियों के बीच

अंतर पर विचार करना छोड़ दिया है, उन्होंने गलती की है। ऐसे मामले हैं जहां यह माना गया है कि किसी गैर-आवेदक के खिलाफ दूसरे पक्ष द्वारा किए गए संदर्भ आवेदन पर कानून के प्रश्नों का संदर्भ मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध है। इनमें शामिल हैं: आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम एस.के.श्रीनिवासन (1970) 75 आई.टी.आर. 93 और आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम रामदास फार्मेसी, (1970) 31 आई.टी.आर. 87। मामले विपरीत चरम दृष्टिकोण रखते हैं: आयकर आयुक्त बनाम बंटिया बैंक लिमिटेड, आई.टी. रेफ.न.20 ऑफ़ 1950 निर्णित 10-10-50 इसके बाद गिरधर दास एंड कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) और शैक्षणिक और नागरिक सूची रिजर्व फंड नंबर 1, उदयपुर के महामहिम महाराणा भागवत सिंह और अन्य बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली (1964) 51 आई.टी.आर. 112 और राजस्थान, श्रीमती धीरजबेन आर अमीन बनाम आयकर आयोग, गुजरात द्वितीय, अहमदलियाड (1968) 70 आई.टी.आर. 194 और संपत्ति कर आयुक्त, गुजोर्म द्वितीय बनाम श्रीमती अरुंधति बालकृष्ण (1968) 70 आई.टी.आर. 203। पिछले मामले में इस न्यायालय द्वारा धन कर आयुक्त, गुजरात बनाम अरुंधति जे. बालकृष्ण (1970) 77 आई.टी.आर 505 के मामले में दिए गए फैसले की पुष्टि की गई थी, लेकिन पहले उठाए गए मुद्दे पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। बैंटिया बैंक लिमिटेड (सुप्रा) में टिप्पणियों से पता चलता है कि उच्च न्यायालय एक विजेता पार्टी को कानून के प्रश्न उठाने के अधिकार से वंचित करने की संभावना के प्रति सचेत था, जो आगे के प्रश्नों के रूप में उचित रूप से उठ सकते थे क्योंकि वे इसमें घनिष्ठ

रूप से शामिल होंगे। आवेदक के आग्रह पर संदर्भित प्रश्नों पर निर्णय, लेकिन यह ऐसे मामले को उस मामले से अलग वर्गीकृत करने में विफल रहा जहां एक गैर-आवेदक कानून के स्वतंत्र और असम्बद्ध प्रश्न उठाना चाहता है। जिन मामलों में दो श्रेणियों के बीच अंतर देखा गया था, लेकिन संदर्भ के लिए आवेदन किए बिना कानून का सवाल उठाने के विजेता पक्ष के अधिकार पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई थी, आयकर आयुक्त बनाम जीवाजी राव शुगर कंपनी लिमिटेड, (1969) 71 आई.टी.आर. 319 हैं। आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश बनाम डॉ. फ़िदा हुसैन जी. अब्बासी (1969) 71 आई.टी.आर 314 और आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम के. रथमान नादर (1969) 71 आई.टी.आर. 433 में इसका पालन किया गया। आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल बनाम एके दास (1970) 77 आई.टी.आर. 31, 44 मामले में दो श्रेणियों के बीच अंतर पर कुछ ध्यान दिया गया है।

वर्तमान मामले में, यह प्रश्न कि क्या 31 मार्च, 1958 को संचित लाभ का निर्धारण करते समय कर के लिए 11,000 रुपये और लाभांश के लिए 6,900 रुपये के प्रावधान को ध्यान में रखा जा सकता है, इस प्रश्न से संबंधित नहीं है कि क्या संचित लाभ में लिया जा सकता है वर्तमान लाभ. दोनों प्रश्नों में अलग-अलग और विशिष्ट राहतें देना शामिल है और एक प्रश्न पर निर्णय दूसरे प्रश्न पर निर्णय को प्रभावित नहीं करता है।

तदनुसार, हम मानते हैं कि अपीलीय न्यायाधिकरण दूसरे प्रश्न को संदर्भित करने के लिए सक्षम नहीं था, और उस सीमा तक संदर्भ को शून्य

माना जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में, दूसरे प्रश्न की गुणवत्ता के आधार पर जांच करना आवश्यक नहीं है। उच्च न्यायालय के फैसले को तब तक अलग रखा जाना चाहिए जब तक इसमें दूसरे प्रश्न पर उसकी राय शामिल हो।

तदनुसार, अपील को इस हद तक अनुमति दी जाती है कि दूसरे प्रश्न पर उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द कर दिया जाता है जबकि पहले प्रश्न पर निर्णय के संबंध में अपील खारिज कर दी जाती है। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

एनके. ए.

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई ।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक श्री विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****